राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

डी. बी. विशेष अपील रिट याचिका सं. 1013/2023

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के माध्यम से राजस्थान राज्य।

2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा।

3. प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, रीथ, तहसील कोटडी, भीलवाड़ा---अपीलकर्ता

बनाम

अब्दुल गफ्फार पुत्र जान मोहम्मद, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी नेहरू नगर, कोटडी, तहसील कोटडी, भीलवाड़ा--- उत्तरदाता

अपीलार्थी (ओं) के लिएः- श्री पंकज शर्मा, ए.ए.जी., श्री ऋषि सोनी

उत्तरदाता (ओं)के लिएः- श्री विनय जैन, श्री दर्शन जैन

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव
माननीय न्यायाधीश श्री मदन गोपाल व्यास

निर्णय

(रिपोर्ट योग्य)

30/01/2024

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 06.01.2023 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता राज्य को प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता को वही लाभ देने का निर्देश दिया गया है, जैसा कि अन्य कर्मचारियों, अर्थात् हेमराज और दुर्गा लाल खटिक के मामले में दिया गया है।

2. अनावश्यक विवरणों से वंचित, इस मामले के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता को शुरू में दैनिक मजदूरी के आधार पर 10.12.1985 को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। समय के साथ, प्रत्यर्थी को नियमित करने के लिए विचार किया गया और उनकी सेवाओं को 31.03.1994 से नियमित किया गया। इसके बाद उन्होंने 9 साल की सेवा पूरी करने पर 08.09.2003 के आदेश के अनुसार चयन ग्रेड अर्जित किया। 18 साल की सेवा पूरी करने पर क्रमिक चयन श्रेणी भी प्रदान की गई। प्रत्यर्थी को 29.06.2010 को LDC के पद पर पदोन्नत किया गया था।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के साथ नियुक्त किए गए दो अन्य दैनिक वेतन कर्मचारियों, दुर्गा लाल खटिक और हेमराज ने एक औद्योगिक विवाद उठाया था और श्रम न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में एक निर्णय पारित किया गया था, जिसमें उन्हें नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमित नियुक्ति का लाभ दिया गया था, यानी उस तारीख से जब उन्हें दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था। राज्य ने रिट याचिका दायर करके पुरस्कार को असफल रूप से चुनौती दी जिसे खारिज कर दिया गया। हालाँकि एक रिट अपील दायर की गई थी, लेकिन अभियोजन के अभाव में उसे भी खारिज कर दिया गया था।

4.ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का लाभ दुर्गा लाल खटिक और हेमराज को दिया गया था, तो याचिकाकर्ता ने राहत की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की कि उन्हें नियमित नियुक्ति का लाभ भी दिया जाए, जिसमें नियमित वेतनमान और अन्य लाभ शामिल हैं। रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई है, जिससे इस अपील को बढ़ावा मिला है।

5. राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि जहां तक दुर्गा लाल खटिक और हेमराज का संबंध है, उन्होंने प्रारंभिक तिथि से नियमित नियुक्ति का लाभ प्राप्त करने के अधिकार सहित विभिन्न अधिकारों का दावा करते हुए एक औद्योगिक विवाद उठाया था और सफल रहे, जबकि यहां रिट याचिकाकर्ता ने कानून के तहत किसी भी उपाय का सहारा नहीं लिया, लेकिन उन्हें 31.03.1994 से नियमित करने के लिए उत्तरदाताओं की कार्रवाई में सहमति व्यक्त की और उस आधार पर उच्च वेतनमान, चयन श्रेणी और पदोन्नति जैसे क्रमिक लाभों का अनुदान। वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि दुर्गा लाल खटिक और हेमराज के पक्ष में पारित पुरस्कार और इस न्यायालय द्वारा पारित बाद के आदेशों को आरईएम में आदेश नहीं कहा जा सकता है, लेकिन केवल उन कार्यवाही के पक्षों के संबंध में लागू थे। इसलिए, उन आदेशों को यह दावा करने का आधार नहीं बनाया जा सका कि रिट याचिकाकर्ता को भी लाभ दिया जाना चाहिए।

6. राज्य के विद्वान वकील का दूसरा निवेदन यह है कि भले ही यह माना जाता है कि दैनिक मजदूरी के आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित करने का निर्देश देने वाले दुर्गालाल खटिक और हेमराज के पक्ष में पारित किए गए निर्णय को पारित किया जा सकता है, लेकिन अब राजस्थान राज्य और अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी [2009 (12) एस. सी. सी. 49] के मामले में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखते हुए कानूनी स्थिति बदल गई है। अब यह एक तय कानूनी स्थिति है कि नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियमित नियुक्ति से पहले की तारीख से नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा सकता है और किसी भी मामले में दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्ति की तारीख से ऐसा कोई लाभ नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत केवल समानता के आधार पर नहीं दी जा सकती है और यह कानून के विपरीत आदेश जारी करने के बराबर होगा। राज्य के विद्वान वकील ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव और अन्य [2015 (1) एस. सी. सी. 347] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील हमारे सामने तर्क देंगे कि रिट याचिकाकर्ता दुर्गालाल खटिक और हेमराज को दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किया गया था और उन्हें सेवा में जारी रखा गया था। भले ही रिट याचिकाकर्ता ने अपने मामले में पारित आदेशों को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना, एक बार जब समान रूप से स्थित कर्मचारियों के पक्ष में एक निर्णय पारित किया गया, जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिए जाने के बावजूद अंतिमता प्राप्त की, तो राज्य एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते, वर्तमान रिट याचिकाकर्ता सहित सभी कर्मचारियों के मामले में दुर्गालाल खटिक और हेमराज के मामले में पारित आदेशों की भावना को लागू करने के लिए कानून के तहत बाध्य था, भले ही उसने दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमितीकरण के अनुदान को चुनौती देने वाली कोई याचिका दायर नहीं की थी। वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि अरविंद कुमार श्रीवास्तव (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रत्यर्थियों के मामले का समर्थन करता है क्योंकि यह सामान्य नियम

घोषित किया गया है कि जब कर्मचारियों के एक विशेष समूह को अदालत द्वारा राहत दी जाती है, तो अन्य सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को उस लाभ को बढ़ाकर समान व्यवहार किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करना भेदभाव और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

8. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

9. निर्विवाद रूप से, रिट याचिकाकर्ता को वर्ष 1985 में समेकित वेतन पर दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ता को बाद में वर्ष 1994 में सेवा में नियमित किया गया। यह भी विवाद में नहीं है कि सेवा में नियमितीकरण के समय, नियमितीकरण का लाभ केवल आदेश की तारीख से दिया गया था, अर्थात 31.03.1994 से और उससे पहले नहीं, दैनिक मजदूरी के आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से बहुत कम। जहां तक नियमितीकरण की तारीख का संबंध है, प्रतिवादी ने उत्तरदाताओं की कार्रवाई को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने स्वीकार किया और सेवा में बने रहे। इसके बाद, उन्हें वेतनमान और पदोन्नति के क्रमिक लाभ इस आधार पर दिए गए कि वे पहले से ही 31.03.1994 से नियमित कर्मचारी थे। उन्होंने उत्तरदाताओं की कार्रवाई को चुनौती दिए बिना इन सभी आदेशों और लाभों को स्वीकार कर लिया और किसी भी मंच पर यह दावा नहीं किया कि वह सेवा में नियमित होने के हकदार हैं और उन्हें दैनिक मजदूरी के आधार पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित नियुक्ति देकर चयन श्रेणी, उच्च वेतनमान, पदोन्नति के लाभों सहित सभी लाभ प्रदान किए।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि दो कर्मचारियों, दुर्गालाल खटिक और हेमराज ने एक औद्योगिक विवाद उठाया था और उनके पक्ष में एक निर्णय पारित किया गया था। हालाँकि इस न्यायालय के समक्ष

किसी भी पक्ष द्वारा निर्णय की प्रति दायर नहीं की गई है, लेकिन यह बताया गया है कि निर्णय में दुर्गालाल खटिक और हेमराज को दैनिक मजदूरी के आधार पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया था। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील इस बात से संतुष्ट नहीं हो सके कि श्रम न्यायालय या रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि लिखित रूप में एक आदेश था। हम दुर्गालाल खटिक और हेमराज के मामले से संबंधित किसी भी आदेश से यह नहीं पाते हैं कि उन आदेशों को सभी समान रूप से स्थित कर्मचारियों पर लागू करने का निर्देश दिया गया था, भले ही उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया हो या नहीं।

11. जगदीश नारायण चतुर्वेदी (उपरोक्त) के मामले में, निर्धारित सिद्धांत यह है कि नियमित नियुक्ति के दावे को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि नियुक्ति नियमों के अनुसार पर्याप्त क्षमता में नहीं की गई हो।

12. दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में प्रत्यर्थी की नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण नियुक्ति नहीं कहा जा सकता है। जाहिर है, प्रत्यर्थी के मामले को नियमित करने के लिए विचार करने का मतलब है कि वह एक नियमित कर्मचारी नहीं था। यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि नियुक्ति कानून के तहत निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियमित वेतनमान में नियमित क्षमता में की गई थी। वास्तव में, यदि याचिकाकर्ता का ऐसा कोई दावा है, तो उसे ऐसा दावा करने से कोई नहीं रोक सकता। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के अपने आदेश को चुनौती नहीं दी। रिट याचिका में ऐसा कोई दावा नहीं है कि याचिकाकर्ता को नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। रिट याचिका में एक स्पष्ट कथन है कि याचिकाकर्ता को दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किया गया था। दावे का एकमात्र आधार, जैसा कि रिट याचिका में

कहा गया है, यह है कि चूंकि दुर्गालाल खटिक और हेमराज के पक्ष में पहले से ही एक निर्णय पारित किया जा चुका था, इसलिए समानता के आधार पर, रिट याचिकाकर्ता को राहत दी जानी चाहिए।

13. यह तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, हमारे विचार में, एक व्यक्ति जिसे दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किया गया है, स्थायी कानूनी स्थिति को देखते हुए, यह दावा नहीं कर सकता है कि बाद में उसका नियमितीकरण दैनिक मजदूरी के आधार पर उसकी नियुक्ति की मूल तिथि से संबंधित होना चाहिए।

14. जगदीश नारायण चतुर्वेदी (उपरोक्त) के मामले में, न्यायालय ने मामले के विशिष्ट तथ्यों के आलोक में दावे की वैधता की भी जांच की। यह ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता हालांकि नियमितकरण के आदेश को पारित किए जाने पर चुनौती दे सकता था, नियमितकरण के आदेश और उससे होने वाले लाभों को कोई चुनौती नहीं थी। रिट याचिकाकर्ता के मामले की जांच निम्नानुसार की गई थीः-

"16. रिट याचिकाकर्ताओं के रास्ते में एक और बाधा है। जब नियमितीकरण का आदेश पारित किया गया था, तो प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार प्रारंभिक नियुक्ति एक महत्वपूर्ण नियुक्ति थी। यदि यह स्थिति थी, तो प्रवीणता परीक्षा देने की आवश्यकता थी जो निर्विवाद रूप से सभी उत्तरदाताओं ने ली है। यदि शुरुआत में नियुक्ति एक महत्वपूर्ण नियुक्ति थी, तो प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता नियमित करने के आदेश को पारित किए जाने पर चुनौती दे सकते थे। नियमितीकरण के आदेश और उससे होने वाले लाभों के लिए कोई चुनौती नहीं थी और किसी भी मामले में नियमितीकरण के आदेश के लिए कोई चुनौती नहीं थी। यदि प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो इसका मतलब होगा कि उनके मामलों में नियमितीकरण बहुत पहले

कर दिया गया था। प्रासंगिक समय पर कोई चुनौती नहीं थी। इसलिए, केवल तदर्थ या कार्य प्रभार सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए विलंबित दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

15. अरविंद कुमार श्रीवास्तव (ऊपर) के मामले में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैंः "22. यह मानते हुए कि उत्तरदाताओं ने भी सेवानिवृत्ति स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की थी, यू. पी. जल निगम की अपील को निम्नलिखित कारणों से अनुमति दी गई थीः-

22. अपीलार्थियों और उत्तरदाताओं दोनों द्वारा उद्धृत उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से जो कानूनी सिद्धांत सामने आते हैं, उनका सारांश नीचे दिया जा सकता हैः-

22. 1 सामान्य नियम यह है कि जब कर्मचारियों के एक विशेष समूह को न्यायालय द्वारा राहत दी जाती है, तो अन्य सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को उस लाभ को बढ़ाकर समान व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। ऐसा न करना भेदभाव के बराबर होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस सिद्धांत को सेवा मामलों में अधिक जोरदार तरीके से लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर विकसित सेवा न्यायशास्त्र यह मानता है कि सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए, सामान्य नियम यह होगा कि केवल इसलिए कि अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों ने पहले न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था, उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

22. 2 तथापि, यह सिद्धांत विलंब और विलम्ब के साथ-साथ स्वीकृति के रूप में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवादों के अधीन है। जिन व्यक्तियों ने अपने मामलों में गलत कार्रवाई को चुनौती नहीं दी और उसे स्वीकार कर लिया और लंबे विलंब के बाद केवल इस कारण से जाग गए कि उनके समकक्ष जिन्होंने समय पर अदालत का

दरवाजा खटखटाया था, वे अपने प्रयासों में सफल रहे, तो ऐसे कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकते कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों के मामले में दिए गए फैसले का लाभ उन्हें दिया जाए। उन्हें बाड़ लगाने वाले के रूप में माना जाएगा और देरी, और/या सहमति, उनके दावे को खारिज करने के लिए एक वैध आधार होगा।

22. 3 तथापि, यह अपवाद उन मामलों में लागू नहीं हो सकता है जहां न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को लाभ देने के इरादे से दिया गया था, चाहे वे न्यायालय गए हों या नहीं। इस तरह की घोषणा के साथ अधिकारियों पर यह दायित्व डाला जाता है कि वे स्वयं सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को इसका लाभ दें। ऐसी स्थिति तब हो सकती है जब निर्णय का विषय नीतिगत मामलों को छूता है, जैसे कि नियमितीकरण की योजना और इसी तरह (के. सी. शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ (उपरोक्त) देखें। दूसरी ओर, यदि न्यायालय का निर्णय व्यक्तिगत रूप से यह अभिनिर्धारित करता है कि उक्त निर्णय का लाभ न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को प्राप्त होगा और इस तरह का इरादा निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है या यह निहित रूप से निर्णय की अवधि और भाषा से पता लगाया जा सकता है, तो जो लोग उन्हें दिए गए उक्त निर्णय का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें यह संतुष्ट करना होगा कि उनकी याचिका में किसी भी तरह की देरी या सहमति नहीं है।

16. कानून के उपरोक्त स्थापन को ध्यान में रखते हुए, हालांकि सामान्य नियम यह है कि जब कर्मचारियों के एक विशेष समूह को अदालत द्वारा राहत दी जाती है, तो अन्य सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को उस लाभ को बढ़ाते हुए समान व्यवहार करने की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ, एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवाद के रूप में, यह माना गया है कि वे व्यक्ति जिन्होंने अपने मामलों में गलत कार्रवाई को चुनौती नहीं दी और उसी को स्वीकार

कर लिया और लंबे समय बाद जाग गए, केवल इस कारण से कि उनके काउंटर पार्ट्स, जिन्होंने पहले समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, अपने प्रयासों में सफल रहे, तो ऐसे कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकते कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों के मामले में दिए गए फैसले का लाभ उन्हें दिया जाए, क्योंकि उन्हें बाड़ लगाने वाले के रूप में माना जाएगा और

17. यह भी देखा जाना चाहिए कि वर्तमान, दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों को समान रूप से नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से वेतनमान के नियमितीकरण का लाभ देने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने वाले न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का मामला नहीं है। इसलिए, इस न्यायालय के लिए प्रतिवादी के विद्वान वकील की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि दुर्गालाल खटिक और हेमराज को जो लाभ दिया गया था, उसे भी उसे दिया जाना चाहिए।

18. सिद्धांतों पर, हम प्रतिवादी की प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से देश के कानून का उल्लंघन होगा। एक बार यह अभिनिर्धारित हो जाने के बाद कि दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उनकी नियुक्ति नियमों के अनुसार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो जाती है, समानता के दावे पर ऐसा कोई भी लाभ प्रदान करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के खिलाफ अनिवार्य रिट जारी करने के बराबर होगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी है। किसी भी चीज़ से अधिक, प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता की ओर से उसे राहत देने में भी बड़ी बाधा होती है।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, इसे दरकिनार किया जा सकता है। हम उसी के अनुसार ऐसा करते हैं। प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका परिणामी रूप से लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दी जाती है,

20. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

(मदन गोपाल व्यास), जे (मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव), एसीजे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।